



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, ३ दिसम्बर, १९९६/१२ अग्रहायण, १९१८

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-१७१००४, ३ दिसम्बर, १९९६

संख्या १-६४/९६-वि० स०—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, १९७३ के नियम १३५ के अन्तर्गत भारतीय वन (हिमाचल प्रदेश तृतीय संशोधन) विधेयक, १९९६ (१९९६ का विधेयक संख्यांक ३०)

जो आज दिनांक 3 दिसम्बर, 1996 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करन हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/-

सचिव ।

भारतीय वन (हिमाचल प्रदेश तृतीय संशोधन) विधेयक, 1996

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सैतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय वन (हिमाचल प्रदेश तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1996 है ।

संक्षिप्त
नाम ।

2. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52-आ में,—

धारा 52-
आ का
संशोधन ।

(क) उप-धारा (1) में—

(i) “गया है,” शब्दों और चिन्ह के पश्चात् “और यान के स्वामी को” शब्द जोड़े जाएंगे ; और

(ii) उप-धारा (1) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु उसके रजिस्ट्रीकृत स्वामी को लिखित रूप से नोटिस देने और उसके आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् के सिवाय, किसी मोटर यान के अधिहरण का आदेश नहीं किया जाएगा ।”

(ख) उप-धारा (2) में “अपनी,” शब्द और चिन्ह के पश्चात् आए शब्दों के स्थान पर “या उसके एजेंट, यदि कोई हो, या औजार, रस्सी, जंजीर, नाव अथवा यान के भार-साधक व्यक्ति की जानकारी या मौनानुकूलता के बिना, किया गया था” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष 1991 में, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय वन अधिनियम, 1927 का सरकारी वनों से, लकड़ी, खैर लकड़ी, राल और कत्था की तस्करी के मामलों में, वन अधिकारियों की सम्पत्ति, औजार (उपकरण) और यानों आदि के अधिहरण की शक्तियां प्रदत्त करने के लिए संशोधन किया गया था। अब यह पाया गया है कि औजारों (उपकरणों), नावों इत्यादि सहित सम्पत्ति अधिहरण के उपबन्ध का अपराधियों पर वांछनीय प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 52-आ में विशेष कमी के कारण न्यायालयों में मामले सफल नहीं हो रहे हैं। महत्वपूर्ण वन सम्पदा के परिरक्षण के लिए विद्यमान उपबन्ध की कमी को दूर करना आवश्यक हो गया है। इसलिए वन सम्पदा के हित में, ऐसे अपराध के लिए यानों के स्वामियों का दायित्व नियत करने के लिए विद्यमान धारा 52-आ में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

सन्त राम,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

3 दिसम्बर, 1996.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधिनियमित होने से राजकोष पर कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्बलित नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 30 of 1996.

THE INDIAN FOREST (HIMACHAL PRADESH THIRD AMENDMENT) BILL, 1996

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Indian Forest Act, 1927 (Central Act No. 16 of 1927) in its application to the State of Himachal Pradesh.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh in the Forty-seventh year of the Republic of India, as follows :—

1. This Act may be called the Indian Forest (Himachal Pradesh Third Amendemnt) Act, 1996. Short title

2. In section 52-B of the Indian Forest Act, 1927,—

Amendment
of section
52-B.

(a) in sub-section (1)—

(i) after the words “it is seized,” the words “and the owner of the vehicle” shall be added; and

(ii) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided that no order confiscating a motor vehicle shall be made except after giving notice in writing to the registered owner thereof and considering his objections, if any.”

(b) In sub-section (2)—

for the words and signs “his agent, if any, and the person-in-charge, of the tool, rope, chain, boat or vehicle and that each of them had taken all reasonable and necessary precaution against such use”, the words and signs, “or his agent, if any, or the person-in-charge of the tool, rope, chain, boat or vehicle” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the year 1991, the Indian Forest Act, 1927 was amended in its application to the State of Himachal Pradesh to confer the forest officers the powers of confiscation of property, tools and vehicles etc. in cases involving smuggling of timber, khair wood, resin and katha from the Government forests. Now it has been found that the provision for confiscation of property alongwith tools, boats and vehicles etc. do not have the desired effect on the offenders and the cases are not being sustained in the Courts of Law because of peculiar lacunae in section 52-B of the Act *ibid*. To preserve the material forest wealth it has become essential to do away with the deficiency in the existing provisions. Therefore, it is necessary in the interest of forest wealth to bring the changes in the existing section 52-B in order to fix the liability of the owner of the vehicles for such offence.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

SANT RAM,
Minister-in-charge.

SHIMLA :
The 3rd December, 1996.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions contained in the Bill when enacted will not involve any extra expenditure out of the State exchequer.

DELEGATED LEGISLATION

-Nil-